मानसून के तेवर से सकते में सरकार

- खरीफ सीजन के लिए धान और सोयाबीन का रकबा घटाया
- बोवनी के लिए 10 टारगेट रखा, वह भी पूरा होना मुश्किल

कन्हैया लोधी

भोपाल, 16 जुलाई. मानसून के तेवर ने मप्र सरकार को सकते में ला दिया है. वैसे तो राज्य सरकार पहले ही मानसून की बेरुखी के अंदेशे से सतर्क हो गई थी. जिसके चलते खरीफ सीजन की दो मुख्य फसलें धान और सोयाबीन का रकबा पहले ही कम कर दिया गया है. लेकिन अब सरकार की दूसरी बड़ी चिंता यह है कि इन दोनों ही फसलों की बोनी के लिए जो टारगेट रखा है, वह पानी की कमी के चलते पूरी होती नजर नहीं आ रही है. ऐसे में अब सरकार कंटीजेंसी प्लान की तैयारी में लग गई है.

वैसे तो किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने मौजूदा खरीफ सीजन के लिए 150.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोवनी का लक्ष्य रखा है जो कि पिछले सीजन के मुकाबले 5.62 लाख हेक्टेयर अधिक है. यह भी पहली बार हुआ है कि प्रदेश में खरीफ सीजन में बोवनी के कुल क्षेत्रफल का आंकड़ा डेढ़ करोड़ हेक्टेयर को पार कर गया है, लेकिन अब कृषि विभाग के अफसरों के मुताबिक बोवनी के इस लक्ष्य को हासिल करना अब आसान नहीं होगा.

भले ही आंकड़ों में कुछ भी दर्ज कर लिया जाए, जिस तरह खरीफ सीजन में मानसून की बेरुखी बनी हुई है, उससे प्रदेश के कमोबेश सभी क्षेत्रों में बोवनी प्रभावित हो रही है. अधिकारियों के मुताबिक यदि अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो फिर आकस्मिक योजना को अमल में लाने की तैयारी की जा चुकी है. ऐसे में किसानों को ऐसी फसलों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जो कि कम अवधि में तैयार हो जाती है और उनको पानी की जरुरत भी कम पड़ती है. सरकार मानसून की बेरुखी की स्थिति में सभी विकल्पों के लिए तैयार है.

सोयाबीन की 6 लाख हेक्टेयर कम क्षेत्र में बोनी

प्रदेश में खरीफ सीजन में सबसे अधिक क्षेत्र में ली जाने वाली फसल सोयाबीन है. प्रदेश में सोयाबीन की बोवनी का नार्मल एरिया 60.18 लाख हेक्टेयर है. लेकिन सरकार ने इस बार बोवनी का रकबा घटाकर 54.09 लाख हेक्टेयर कर दिया है जो कि पिछले वर्ष के 54.70 लाख हेक्टेयर से भी कम है. लेकिन अब तक लगभग 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही बोवनी की जा सकी है. सबसे बड़ी बात ये कि जहां ये फसल लगी है, वहीं अब पानी की किल्लत भी होने लगी है, जिससे आने वाले दिनों में बोवनी के साथ ही उत्पादन भी प्रभावित होने का अंदेशा बन गया है.

75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही अब तक बोवनी

खरीफ सीजन में बोवनी का सीजन लगातार निकल रहा है, अब तक प्रदेश में महज 75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही बोवनी किया जा सका है. यानी अभी लगभग आधा सफर ही तय हुआ है. पिछले वर्ष प्रदेश में 144.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोवनी की गई थी, वहीं खरीफ के लिए सामान्य रकबा 145.98 लाख हेक्टेयर है. इस बार राज्य सरकार ने दलहन और तिलहन दोनों ही फसलों की बोवनी का रकबा बढ़ा दिया है. दलहन का रकबा 5.28 लाख से बढ़ाकर 8.27 लाख हेक्टेयर किया गया है, वहीं तिलहन बोवनी का रकबा 60.82 लाख से बढ़ाकर 63.06 लाख हेक्टेयर किया गया है.

धान का एरिया ढाई लाख हेक्टेयर घटाया

मौसम विभाग ने पहले ही कमजोर मानसून का अंदेशा जता दिया था, लिहाजा राज्य सरकार ने इस बार पहले ही धान और सोयाबीन बोवनी का लक्ष्य घटा दिया है. ये दोनों ही फसलें खरीफ सीजन की सबसे मुख्य फसल है. लेकिन इस बार धान की बोनी का लक्ष्य 2.47 लाख हेक्टेयर तक घटा दिया गया है. पिछले वर्ष प्रदेश में 42.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोवनी की गई थी, लेकिन इस बार महज 39.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही बोवनी का टारगेट रखा गया है. लेकिन अब तक की अवधि में बमुश्किल 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही बोनी की जा सकी है, जो कि पिछले सीजन के मुकाबले आधा भी नहीं है. गुजरते वक्त के साथ देर तक पकने वाली किस्मों के रोपण के लिए समय भी निकल रहा है.

पुराने पुल से नदी में गिरी एम्बुलेंस, चालक समेत दो घायल

मैहर, 16 जुलाई. मध्यप्रदेश के मैहर जिले के उचेहरा थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक एम्बुलेंस पुराने पुल से नीचे नदी में गिर गई. हादसे में चालक समेत दो लोग घायल हो गए.

पुलिस सूत्रों के अनुसार एम्बुलेंस किसी मरीज को लेने जा रही थी. इसी दौरान बरुआ नदी के पुराने पुल से वाहन अनियंत्रित होकर नीचे नदी में जा गिरा. वही नदी में पानी कम होने के कारण चालक शुभम परौहा और एम्बुलेंस में सवार एक अन्य व्यक्ति की जान बच गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल दोनों को एम्बुलेंस से सुरक्षित बाहर निकाला. घायलों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

सत्र के पहले कांग्रेस की बैठक रविवार को

विशेष संवाददाता

भोपाल, 16 जुलाई . विधानसभा के सोमवार से प्रारंभ हो रहे मानसून सत्र को लेकर प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक रविवार 19 जुलाई की शाम नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के शासकीय निवास पर भोपाल में आयोजित होगी. बैठक में विधानसभा सत्र के लिए कांग्रेस की रणनीति तय की जाएगी तथा सरकार को विभिन्न जनहित के मुद्दों पर घेरने की रूपरेखा तैयार की जाएगी.

बैठक में कांग्रेस विधायक राज्य के प्रमुख जनसरोकारों से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह तय करेंगे कि विधानसभा में किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा. पार्टी रोजगार सृजन, भर्ती परीक्षाओं में

सुधार, समान नागरिक संहिता (यूसीसी), अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के अधिकार, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार जैसे विषयों पर सरकार से जवाब मांगेगी.

इसके साथ ही प्रदेश में सामने आए कथित घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों को भी विधानसभा में जोरदार ढंग से उठाने की तैयारी की जाएगी. कांग्रेस इन मामलों में सरकार से विस्तृत जवाब और जवाबदेही सुनिश्चित करने की रणनीति बनाएगी.

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल जनता की आवाज को पूरी मजबूती से विधानसभा में उठाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा, केन-बेतवा परियोजना तथा आदिवासी और दलित समुदायों के अधिकार जैसे मुद्दे गंभीर चिंता का विषय बन चुके हैं और इन पर सरकार को जवाब देना होगा.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तैयारी और एकजुटता के साथ विधानसभा सत्र में उतरेगी ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग की समस्याओं और अपेक्षाओं को प्रभावी ढंग से सदन में उठाया जा सके.

मुख्यमंत्री का फैसला ज़मीन पर दिखे : पटवारी

विशेष संवाददाता

भोपाल, 16 जुलाई. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा पशुपालन एवं गौ-संवर्धन विभाग अपने पास रखने के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा है कि असली परीक्षा विभाग अपने पास रखने की नहीं, बल्कि इससे प्रदेश में पशुपालन और गौ-कल्याण व्यवस्था में ठोस सुधार लाने की है.

उन्होंने कहा कि विभागों का आवंटन मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि यह निर्णय केवल प्रतीकात्मक साबित होगा या इससे जमीनी स्तर पर

बदलाव भी दिखाई देगा. उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी वर्षों से गौ-सुरक्षा को राजनीतिक प्राथमिकता बताती रही है, लेकिन प्रदेश में गौवंश की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है. गौशालाओं में चारा, पानी, दवाइयों और अन्य आवश्यक संसाधनों की कमी बनी हुई है.

जीतू पटवारी ने विधानसभा में सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों में आवारा मवेशियों से जुड़े 237 सड़क हादसे हुए, जिनमें 94 लोगों की मृत्यु और 133 लोग घायल हुए. उनका आरोप है कि गौशालाओं को मिलने वाली सरकारी सहायता भी प्रति पशु प्रतिदिन होने वाले वास्तविक खर्च, जो लगभग 70 रुपये बताया जाता है, से काफी कम है. उन्होंने मुख्यमंत्री से पशुपालकों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करने, गौशालाओं को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने तथा आवारा मवेशियों की समस्या के समाधान के लिए समयबद्ध कार्ययोजना सार्वजनिक करने की मांग की.

तीन दिनों में साइबर ठगी के 10 मामले

ग्वालियर. शहर में साइबर ठगी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. पुलिस के अनुसार पिछले तीन दिनों में साइबर ठगी के 10 मामले सामने आए हैं. इनमें पड़ाव, मुरार और महाराजपुरा थाना क्षेत्रों के तीन मामलों में पीड़ितों से कुल 2.82 लाख रुपये से अधिक की ठगी की गई है.

पुलिस के अनुसार पड़ाव थाना क्षेत्र की लक्ष्मीबाई कॉलोनी निवासी 29 वर्षीय ललित स्वामी ने शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें अप्रैल में टेलीग्राम के एक समूह में जोड़ा गया था. प्रारंभ में ऑनलाइन कार्य के बदले कुछ राशि देकर विश्वास हासिल किया गया.

हिस्ट्रीशीटर ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार

इंदौर. तुकोगंज पुलिस ने एक हिस्ट्रीशीटर बदमाश को 13.43 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है. जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 1.50 लाख रुपए बताई गई है.

आरोपी के खिलाफ पहले से लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट और मारपीट सहित आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं. धेनू मार्केट वाली गली, नेहरू पार्क के पीछे संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी. इसी दौरान एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा. संदेह होने पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया. पूछताछ में उसने अपना नाम सूरज वर्मा उम्र 30 साल निवासी काजी की चाल बताया. तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक पारदर्शी पन्नी में रखी 13.43 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई.

4 आधुनिक रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन आज

भोपाल, 16 जुलाई . पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल अंतर्गत पुनर्विकसित साँची, विदिशा, अशोकनगर और शिवपुरी रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं और स्थानीय सांस्कृतिक पहचान के साथ विकसित इन स्टेशनों का उद्घाटन दोपहर 3:40 बजे होगा. इससे पहले दोपहर 2 बजे स्टेशन परिसरों में सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, रेलवे अधिकारी, विद्यार्थी और नागरिकों की उपस्थिति में सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुरस्कार वितरण और लघु फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा.

प्रधानमंत्री इस अवसर पर देशभर के 20 राज्यों में विकसित 75 अमृत भारत स्टेशनों का भी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे. लगभग 1,570 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इन स्टेशनों को आधुनिक, यात्री-अनुकूल और स्थानीय विरासत के अनुरूप विकसित किया गया है. मध्यप्रदेश के 13 स्टेशनों में पश्चिम मध्य रेलवे के छह स्टेशन शामिल हैं, जिनमें भोपाल मंडल के साँची, विदिशा, अशोकनगर और शिवपुरी प्रमुख हैं. पुनर्विकास के तहत स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप दिया गया है. प्लेटफॉर्मों पर विस्तृत शेड, आधुनिक बैठने की व्यवस्था, डिजिटल यात्री सूचना प्रणाली, कोच पोजिशन डिस्प्ले बोर्ड, उन्नत पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय, आधुनिक प्रतीक्षालय

> रेलवे के अनुसार पुनर्विकसित स्टेशन न केवल यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, बल्कि क्षेत्रीय पर्यटन, व्यापार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक-आर्थिक विकास को भी नई गति देंगे. उद्घाटन समारोह को भोपाल मंडल और मध्यप्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.

और शुद्ध पेयजल जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं. साथ ही सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग और दिव्यांगजन-अनुकूल सुविधाओं जैसे रैंप एवं टैक्टाइल पाथ का भी निर्माण किया गया है.

इलेक्टिव कोर्स के बिना मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे छात्र

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 16 जुलाई. प्रदेश के सभी आयुर्वेद कॉलेजों को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि बीएएमएस आयुर्वेद स्नातक के 2021-22 बैच के छात्र 9 इलेक्टिव कोर्स क्वालीफाई किये बिना मुख्य यूनिवर्सिटी परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे।

बता दें बीएएमएस की कुल साढ़े 5 साल की डिग्री में 3 प्राफ (हर डेढ़ साल में होने वाली परीक्षा) होती है.

जो कि प्रत्येक डेढ़ साल में होती है. जिसमें सैद्धांतिक व प्रायोगिक परीक्षाओं के अलावा आयोग द्वारा निर्धारित विभिन्न ऑनलाइन इलेक्टिव कोर्स के अंतर्गत प्रति प्रॉफ 3-3 परीक्षाओं में यानी कुल 9 इलेक्टिव कोर्स में पास होना अनिवार्य है। वहीं जानकारी के अनुसार प्रदेश में करीब 900 और भोपाल में 350 छात्रों ने इलेक्टिव कोर्स पूरा नहीं किया है। जिसके बाद छात्रों की ये लापरवाही उन पर भारी पड़ सकती है.

> फिलहाल आयोग ने इलेक्टिव कोर्स पूरा करने के लिये अंतिम तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि इलेक्टिव कोर्स पूरा किये बिना अगर संस्थान मुख्य परीक्षा में छात्रों को शामिल कराते हैं तो दण्डात्मक कार्यवाही हो सकती है। जिसको लेकर आयुष मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ राकेश पाण्डेय ने फाइनल बैच के छात्रों को लापरवाही न बरतने की सलाह दी है.

मध्यप्रदेश में मानसून की रफ्तार हुई धीमी

35 जिलों में बारिश की कमी

19 से तेज वर्षा के आसार

कम बारिश से उमस बढ़ी और लोग हुए परेशान

भोपाल, 16 जुलाई. मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार पिछले एक सप्ताह से धीमी बनी हुई है. लगातार सात दिनों से कहीं भी भारी या अति भारी बारिश नहीं होने के कारण प्रदेश में वर्षा का आंकड़ा सामान्य से पीछे चल रहा है. अब तक प्रदेश में 241.8 मिमी (करीब 9.5 इंच) बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस समय तक औसतन 270.3 मिमी (करीब 10.6 इंच) वर्षा होनी चाहिए थी. वहीं कम बारिश के कारण उमस से लोग परेशान हो रहे.

प्रदेश फिलहाल सामान्य से 11 प्रतिशत कम बारिश के दौर से गुजर रहा है. मौसम विभाग का अनुमान है कि 19 जुलाई से नया मौसम सिस्टम सक्रिय होने के बाद बारिश फिर जोर पकड़ सकती है.

बारिश की सबसे अधिक कमी पूर्वी मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है. जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग सहित 35 जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पूर्वी हिस्से में औसतन 24 प्रतिशत कम बारिश हुई है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में सामान्य से 2 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है. लगातार कम बारिश से खरीफ फसलों, जलाशयों और भूजल स्तर पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है. मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई से उत्तर-पश्चिम भारत में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने और चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से मध्य प्रदेश में मानसून दोबारा सक्रिय हो सकता है.

नशामुक्ति अभियान बना जन आंदोलन

विशेष संवाददाता

भोपाल. मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेश को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए राज्यव्यापी जनजागरूकता अभियान 'नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0' ने पहले ही दिन व्यापक जनसहभागिता दर्ज की. प्रदेशभर में आयोजित 600 से अधिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से करीब 1.85 लाख लोगों तक अभियान का संदेश पहुंचाया गया.

अभियान के तहत विद्यार्थियों, एनसीसी कैडेट्स, पुलिस कर्मियों, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने रैलियों, मैराथन, जागरूकता दौड़, नुक्कड़ नाटक, प्रश्नोत्तरी, हस्ताक्षर अभियान, शपथ ग्रहण कार्यक्रमों तथा जनसंवाद में उत्साहपूर्वक भाग लिया. इंदौर में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के बीच नशामुक्ति का संदेश देने वाला रोबोट कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा. बुरहानपुर में करीब 7,000 लोगों ने मैराथन में भाग लेकर नशे से दूर रहने की शपथ ली, जबकि झाबुआ में आयोजित नशामुक्ति दौड़ में लगभग 5,000 प्रतिभागी शामिल हुए. टीकमगढ़ और विदिशा में जागरूकता रथ, ध्यान सत्र और हस्ताक्षर अभियान आयोजित किए गए, वहीं सीहोर में सोशल मीडिया अभियान के साथ गांव-गांव जनजागरूकता गतिविधियां संचालित की गईं. उज्जैन, धार, खरगोन, आगर-मालवा, जबलपुर, ग्वालियर, खंडवा, छिंदवाड़ा सहित अनेक जिलों में भी विविध कार्यक्रम आयोजित हुए. पचमढ़ी और सागर स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालयों में नवआरक्षक प्रशिक्षुओं को नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई. मध्यप्रदेश पुलिस के अनुसार, अभियान का उद्देश्य नशे के विरुद्ध जनजागरूकता को जनआंदोलन का स्वरूप देना है.

12 वर्षीय साली की हत्या के आरोप में जीजा गिरफ्तार

धार, 16 जुलाई. जिले की बाग थाना पुलिस ने 12 वर्षीय बालिका की हत्या के मामले में फरार चल रहे उसके जीजा को महाराष्ट्र के शाहदा से गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी ने पारिवारिक विवाद के चलते कथित रूप से बालिका की हत्या की थी.

पुलिस के अनुसार 12 जुलाई को ग्राम रिसावला से 12 वर्षीय बालिका के लापता होने की सूचना पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी. जांच के दौरान बालिका का शव पाडलिया घाटी के समीप वन विभाग के एक सीमेंटेड कुएं से बरामद हुआ. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया.

उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर 51 का वेतन कटा

स्वास्थ्य विभाग में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सीएमएचओ की कार्रवाई

सीधी. स्वास्थ्य विभाग में समयबद्ध उपस्थिति, कार्य संस्कृति में अनुशासन तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार खरे ने सार्थक एप में नियमित उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले 51 कर्मचारियों के वेतन कटौती की कार्रवाई की है.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति सार्थक एप के माध्यम से दर्ज की जाती है, जिससे उनकी उपस्थिति एवं कार्यस्थल पर उपलब्धता की नियमित निगरानी की जाती है. समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 51 कर्मचारियों द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सार्थक एप पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की गई. इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित कर्मचारियों के वेतन में नियमानुसार कटौती की गई है. डॉ. खरे ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का समय पर कार्यस्थल पर उपस्थित रहना और डिजिटल उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है. उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन के निर्देशों का पालन नहीं करने तथा लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध आगे भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन निर्धारित समय पर सार्थक एप में अपनी उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करें.

प्रयास | पारिवारिक, संपत्ति और भरण-पोषण संबंधी विवादों के समाधान का प्रभावी मंच

वरिष्ठ नागरिक पुलिस पंचायत ने सुलझाए विवाद

विशेष संवाददाता

भोपाल, 16 जुलाई. मध्यप्रदेश पुलिस की 'देशभक्ति-जनसेवा' की भावना के अनुरूप विदिशा पुलिस द्वारा संचालित सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत वरिष्ठ नागरिकों के पारिवारिक, संपत्ति और भरण-पोषण संबंधी विवादों के समाधान का प्रभावी मंच बनकर उभरी है. इस पहल का उद्देश्य बुजुर्गों को समय पर न्याय, सम्मानजनक जीवन और भावनात्मक सुरक्षा उपलब्ध कराना है.

विदिशा पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के निर्देशन तथा

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे के मार्गदर्शन में आयोजित हालिया पुलिस पंचायत में वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े आठ प्रकरणों की सुनवाई की गई. कोर कमेटी ने सभी मामलों में संवाद, समझाइश और आपसी सहमति के माध्यम से समाधान कराने का प्रयास किया.

सबसे संवेदनशील मामले में एक सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी की विधवा ने आरोप लगाया कि पति की मृत्यु के बाद उनके बेटों ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया, जिससे अंतिम संस्कार के लिए भी उन्हें लोगों से आर्थिक सहायता मांगनी पड़ी. पुलिस की मध्यस्थता के बाद दोनों बेटों ने मां को किसी प्रकार से प्रताड़ित या घर से बेदखल नहीं करने तथा उन्हें पारिवारिक मकान में सम्मानपूर्वक रहने देने और संपत्ति संबंधी भविष्य के निर्णय का अधिकार स्वीकार किया.

शमशाबाद के एक मामले में पुत्र और बहू पर मारपीट के आरोपों का समाधान संपत्ति के मूल्यांकन और उचित मुआवजे पर सहमति के साथ हुआ. कुरवाई में भूमि विवाद के बाद चारों पुत्र अपने पिता के भरण-पोषण के लिए प्रतिमाह दो-दो हजार रुपये देने पर राजी हुए.

राशन घोटाला करने वाले प्रबंधक व विक्रेता को जेल

बड़वानी. गरीबों के हक के राशन में कथित गड़बड़ी करने वाले उचित मूल्य दुकान के प्रबंधक व विक्रेता को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है. बहुचर्चित राशन वितरण अनियमितता प्रकरण में न्यायालय ने पाया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले खाद्यान्न के वितरण एवं स्टॉक में गंभीर अनियमितताएं हुई थी.

मामले के अनुसार जांच के दौरान दुकान के पीओएस रिकॉर्ड और भौतिक स्टॉक के सत्यापन में गेहूं एवं चावल की बड़ी मात्रा कम पाई गई थी. शिकायतों और जांच के बाद प्रबंधक लालसिंह चौहान तथा विक्रेता राजू अलावे के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं आपराधिक न्यास भंग के आरोपों में प्रकरण दर्ज किया था. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने तकनीकी, दस्तावेजी साक्ष्य एवं गवाहों के माध्यम से आरोप सिद्ध किए. विशेष न्यायाधीश एलडी सोलंकी ने 16 जुलाई को दोनों आरोपियों को 4-4 वर्ष के कठौर कारावास तथा 25-25 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया. अर्थदंड अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कठौर कारावास भुगतना होगा. प्रकरण में शासन की ओर से प्रभावी पैरवी अपर लोक अभियोजक जगदीश यादव ने की.